



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]
No. 62]

नई विल्सी, मंगलवार, फरवरी 7, 1978/माघ 18, 1899
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 1978/MAGHA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न थीं जोड़ी हुई रिप्रिंट से इक यह उत्तर संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि व्याय और कानूनी कार्य संबंधी

(विषयालय विभाग)

आदेश

नई विल्सी, 7 फरवरी, 1978

का०आ० 78(अ) ——राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वेषां द्वारा की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है ——

आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के एक निर्वाचित उम्मीदवार, श्री के० मधुसूदन रेड्डी ने 1972 में हुए साधारण निर्वाचितों से लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 'प्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 8क क अधीन, जैमी कि वह निर्वाचन प्रिधि (प्रधानांश) प्रधिनियम, 1975 (1975 का 40) के प्रारम्भ से दोक पूर्व थी, छह वर्ष की प्रवधि के लिये निरहंता उपयोग कर ली है,

और निरहंता को उक्त प्रवधि का प्रयोग नहीं हुआ है,

और उक्त श्री के० मधुसूदन रेड्डी ने उक्त प्रवधि के अनश्वित भाग के लिये निरहंता हटाये जाने के बिन्दुत उक्त प्रधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रपति को एक याचिका प्रस्तुत की है,

और राष्ट्रपति ने उक्त प्रधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुशरण में उक्त याचिका पर निर्वाचन प्रायोग की राय मार्गी है,

और निर्वाचन प्रायोग ने प्राप्ती यह राय (उपार्वन्ध देखिए) दी है कि निर्वाचित उम्मीदवार की उक्त प्रधिनियम की धारा 8क (2) के अधीन दी गई याचिका नामजूर कर दी जाये,

यह प्रव, मै, नीलम सजोव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, उक्त प्रधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन मधुसूदन रेड्डी की प्रवधि विकासीयों का प्रयोग करने हुए, उक्त श्री के० मधुसूदन रेड्डी की याचिका नामजूर करता हूँ।

राष्ट्रपति भवन,
नई विल्सी,
31 जनवरी, 1978

नीलम सजोव रेड्डी,
भारत का राष्ट्रपति

उपार्वन्ध

भारत के निर्वाचन आयोग के समझ

लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 की धारा 8क (2) के साथ पठित धारा 8क (3) के अधीन श्री के० मधुसूदन रेड्डी, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के मामले के सबै में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्णय के विषय में।

राय

यह लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे 'प्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 8क (2) के साथ पठित धारा 8क (3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्वाचित आयोग को प्राप्त एक निर्णय है। श्री के० मधुसूदन रेड्डी का (जिन्हें इसमें आगे निर्वाचित प्रभ्यर्थी कहा गया है) 1972 में आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचित, निर्वाचित प्रभ्यर्थी द्वारा प्रधिनियम की धारा 123(4) के अधीन आप्ट आवारण के प्राधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय उस न्यायालय द्वारा (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के ममक 1972 की निर्वाचन अर्जी सं० 7 से उत्पन्न 1973 की सिविल अपील सं० 389 में) सारीख 20 दिसम्बर, 1974

को दिया गया था। उस निर्णय के कानूनी परिणामस्वरूप, श्री मधुसूदन रेड्डी अधिनियम की धारा 8क, जैसी यह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के ठीक पहले थी, के अधीन संदर्भ या किसी राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का वक्तव्य उन्होंने या हाँने के लिये 6 वर्ष की अवधि के लिये निरहित हो गया और उनकी यह निरहित 19-12-1980 तक बनी रहेगी। अब निर्वाचित अध्यर्थी द्वारा अपनी निरहित को अवधि के बोध भाग के लिये निरहित हटाये जाने के लिये राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई अर्जी पर आयोग को गया मार्गी गई है:

2 मामले के मध्य मध्येप में इस प्रकार है —

(i) निर्वाचित अध्यर्थी 1972 में आधा प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में चेन्नै विधान सभा निर्वाचन थेन द्वारा निर्वाचित अध्यर्थी के रूप में चुना हुआ था। उम्हें अपने प्रतिवृद्धी अध्यर्थी श्रीमती एन० विमला देवी को, जो कांग्रेस की अध्यर्थी थी, 1974 मतों से पराजित किया और उसे निर्वाचित घोषित किया गया था। उसके निर्वाचन को श्रीमती एन० विमला देवी ने आधा प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 1972 को निर्वाचित अर्जी नं० 7 द्वारा चुनती दी थी। उम्ही अर्जी में पहले प्रभिकायन किया गया था कि निर्वाचित अध्यर्थी, उसके अधिकारी और निर्वाचित अध्यर्थी द्वारा उसके निर्वाचन अधिकारी को सहमति से अन्य अवक्त्रों ने ऐसे विभिन्न कार्य किये जो अधिनियम की धारा 123(1), (2), (3), (3क), (4), (5), (6) और (7) में विवरित अधिकारी के विवाद के लिये 20 विवादक बनाये किन्तु उम्ही सभी विवादकों का उत्तर निर्वाचित अध्यर्थी के पक्ष में विद्या लदनुमार उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 22-12-1972 के निर्णय और आदेश द्वारा अर्जी खालिज कर दी।

(ii) आपाल किये जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने इसके समक्ष और दिये गये विवादकों में से एक विवादक पर जो अधिनियम की धारा 123(4) के अर्थ से निर्वाचित अध्यर्थी द्वारा या उसको प्रेरणा से श्रीमती एन० विमला देवी के विरुद्ध मानहानिकारक पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण के गवध में था, दिये गये साध्य पर फिर से विचार किया। उच्चतम न्यायालय ने अधिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने मौजिक साध्य के गुण विवेचन में एक गलत रूप अपनाया और श्रीमती एन० विमला देवी द्वारा दिये गये साध्य को पक्षपातपूर्ण मान कर अविवादनीय माना था, किन्तु निर्वाचित अध्यर्थी के साक्षियों के साक्ष्य के भूल्याकान में इसी प्रकार का मानक लागू नहीं किया। उक्त विवादक पर दिये गये साध्य पर फिर से विचार करने पर उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस मानहानिकारक पुस्तकों पर आधेप किया गया है वह निर्वाचित अध्यर्थी को प्रेरणा पर मुद्रित और वितरित की गई थी। तदनुसार, उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचित अध्यर्थी को अधिनियम की धारा 123(4) के अधीन अधिकारी का दोपी पाया और तारीख 20-12-1974 को उसका निर्वाचन सूच्य घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप निर्वाचित अध्यर्थी धारा 8क, जैसी कि वह उस समय थी, के अधीन 6 वर्ष की अवधि अर्थात् 19-12-1980 तक के लिये निरहित हो गया।

3 निर्वाचित अध्यर्थी ने अपनी निरहित को बोध अवधि के लिये निरहित हटाये जाने के लिये राष्ट्रपति की तारीख 24 अक्टूबर, 1977 को यह अर्जी प्रस्तुत की थी। तारीख 9 दिसंबर, 1977 को निर्वाचित

गदम्य अपने काउन्सेल के साथ मेरे समक्ष बैयक्तिक सुनवाई के लिये उपम्भित हुआ। काउन्सेल ने आग्रह किया कि निर्वाचित अध्यर्थी को बैखते हुए निर्वाचित अध्यर्थी की निरहित हटा नी जाने वाहिंगे, अर्थात् —

- (i) यह कि निर्वाचित अध्यर्थी पर पुस्तकों के मद्रण और वितरण का वाधारण प्रतिनिधायों रूप में निश्चित किया गया है,
- (ii) यह कि निर्वाचित अध्यर्थी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और जन सेवक है जिस पर किसी प्रकार का कलक नहीं है तथा वह सगठन और नेतृत्व के प्रति वफादार रहा है।
- (iii) यह कि वह 10 वर्ष तक पचायत समिति का अध्यक्ष रहा किन्तु विधान सभा में अपना स्थान बनाये रखने के लिये उसे आधा प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप अपना निर्वाचित होने पर, उक्त पद से त्वारपत्र देना पड़ा। उच्चतम न्यायालय का निर्णय बहुत कठोर है क्योंकि वह विधान सभा से भी अपना स्थान खो बैठा है और अब वह किसी सार्वजनिक पद पर नहीं है।
- (iv) यह कि यह इस समय उसको निरहित हटाई नहीं जाती है और राज्य विधान सभा के अग्रणी वर्ष के आरम्भ में हीने वाले माधारण निर्वाचित को लड़ने के लिये उस पाव नहीं जानाया जाता तो वह शास्त्रव में 6 वर्ष से बहुत अधिक अवधि के लिये निरहित रहेगा। क्योंकि उसके पश्चात् वह वर्ष तक निर्वाचित होने की समावना नहीं होगी।

मैंने निर्वाचित अध्यर्थी को और मेरे पेश की गई उक्त दर्शियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। जैसा कि वह आयोग इसके पूर्व कई बार कह चुका है, आयोग ऐसे मामलों में न्यायालय के निर्वाचित से आवद्ध है और वह उस मामले के गुणागुण पर, जो पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया, विचार नहीं कर सकता है। आयोग को ऐसे मामलों में जो बात देखनी होती है वह यह है कि क्या ऐसों कोई अवश्यमनकारी परिस्थितियां हैं जो ऐह वर्ष को पूर्ण अर्थात् पूरी होने के पूर्व उसकी निरहित हटाने के लिये राष्ट्रपति की वैयेकिक शक्तियों के प्रयोग का सम्बुद्ध अधार है। मैं इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा उक्त वैयेकिक शक्ति के प्रयोग के लिये ऐसी कोई अवश्यमनकारी परिस्थिति या विषेष वारण नहीं पाता है और निर्वाचित अध्यर्थी मुझे अपनी उक्त दलोंमें किसी ऐसी अवश्यमनकारी परिस्थिति बताने में समर्थ रहा है। निर्वाचित अध्यर्थी अपने हां कथन के प्रनुसार एक सम्बोधन से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहा है और इसलिये उसे ४५ मासूम होना चाहिए कि रवायत राजीतिक वातावरण बनाये रखने के लिये यह पूर्णतः आवश्यक है कि किसी भी अवधिक को अपने विरोधी का विरोध हनन नहीं करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिये, इस बात से कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पड़ता है कि मानहानिकारक सामग्री किसी व्यक्ति ने स्वयं प्रकाशित या विर्तारस की है या ऐसा उसको प्रेरणा पर किया गया है। जहां तक निर्वाचित अध्यर्थी को, उसके सगठन और नेतृत्व के प्राप्ति निष्ठा सम्बोधी दलील का सबध है यह कहना पर्याप्त होगा कि उसने मेरे समक्ष वैयिकिक सुनवाई के समय यह स्वीकार किया कि निर्वाचित के पूर्व वह कांग्रेस वल का सदस्य था किन्तु उसने उक्त दल द्वारा नामनिविष्ट अध्यर्थी के विरुद्ध निर्वाचित लड़ने के लिये उक्त दल छोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त निर्वाचित अध्यर्थी की यह इसीले कि उसके पास कोई सार्वजनिक पद नहीं रहा है, निरहित हटाई जाने के लिये कोई आधार नहीं है क्योंकि सार्वजनिक पद धारण करना निष्कृप्त जनरेवा के लिये पूर्णिमा नहीं है। इसी प्रयोग यह दलील भी वि-1978 के आधार में होने वाले प्रगति साधारण निर्वाचित के पश्चात् अनेक वर्षों तक निर्वाचित नहीं हो सकेंगे, निरहित हटा नी जाने को कि साधारण अनुक्रम में वर्ष 1980 के अन्त तक जनरेवा संघभग, तीन वर्ष पहले ही समाप्त कर देने के लिये पर्याप्त कारण नहीं है। पूर्वाप्त जानी को ध्यान में रखते हुए भेरो राय यह है कि निर्वाचित अध्यर्थी की निरहित

को समय से पूर्व नहीं हटाया जाना चाहिये श्रीग वह 6 बर्षों की पूरी अधिकारी के लिये बनी रहने दी जाए। हाल ती में, एक अन्य भास्त्रों में (जो कि पंजाब के एक भूतपूर्व विधायक थे) जसदेव सिह से सबैक्षण हैं) जो एक पुराने के प्रकाशन में सबैक्षण इसी प्रकार का मामला था, और जिसमें अधिनियम की धारा 123(3) और (उके) के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया था, आयोग द्वारा दो गई राय पर राष्ट्रपति ने निरहेता हटायें जाने की अर्जी नाप्रयुक्त कर दी थी।

5 अन्त में, मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि निवाचित क्षेत्र के कुछ मनदानकारी ने जिनका प्रतिनिधित्व थी एम० वेकटनराम० अध्यक्ष, फिरान सेवा सोसाइटी (रजिं०) [फारमर्स सर्विस सोसाइटी (रजिं०)], कोडाकाल्ला, वाराणसी, जिला (आ०प्र०) ने किया था, आयोग को यह अध्यावेदन किया था कि निवाचित अध्यर्थी ओं के० मधुसूदन रेड्डी की इस अर्जी को मजूर नहीं किया जाना चाहिये। ऐसी थी, यो मधुसूदन रेड्डी को० मुक्त अर्जी पर इसके पूर्व अभिव्यक्ति प्रपनी राय को द्यान में रखते हुए उनके अध्यावेदन में बताये गये आवागो का उल्लेख नहीं करता चाहता।

6 तत्त्वगत, गैं लाग प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन यह राय देना है कि श्री के० मधुसूदन रेड्डी द्वारा उपर्युक्त निरहेता उक्त अधिनियम की धारा 8क(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा न हटाई जाये।

नई विली.

15 दिसंबर, 1977

गैं एम० एल० शक्ति
भारत के० मुख्य निर्वाचन आयोग

[गैं एफ० 7(3)/78-वि०-11]

के० वै० मुन्द्रम्, सलिल

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

ORDER

New Delhi, the 7th February, 1978

S.O. 78(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

Whereas Shri K. Madhusudan Reddy, a returned candidate to the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh at the general elections held in 1972, has incurred disqualification for a period of six years under section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the said Act) as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975).

And whereas the said period of disqualification has not expired;

And whereas the said Shri K. Madhusudan Reddy has submitted a petition to the President under sub-section (2) of section 8A of the said Act for the removal of the disqualification for the unexpired portion of the said period;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission on the said petition in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the petition of the returned candidate under section 8A(2) of the said Act be rejected;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-

section (3) of section 8A of the said Act do hereby reject the petition of the said Shri K. Madhusudan Reddy.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi,
January 31, 1978.

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re :—Reference from the President under Section 8A(3) read with Section 8A(2) of the Representation of the People Act, 1951 regarding the case of Shri K. Madhusudan Reddy, ex-member of Andhra Pradesh Legislative Assembly.

OPINION

This is a reference to the Election Commission from the President of India under Section 8A(3) read with Section 8A(2) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the Act). The election of Shri K. Madhusudan Reddy (hereinafter referred to as the returned candidate) to the Legislative Assembly of Andhra Pradesh in 1972 had been set aside by the Supreme Court on the ground of commission of corrupt practice under section 123(4) of the Act by the returned candidate. The decision of the Supreme Court (in Civil Appeal No. 389 of 1973 arising out of election Petition No. 7 of 1972 before the Andhra Pradesh High Court) was given by that Court on 20 December, 1974. As a legal consequence of that decision, Shri Madhusudan Reddy incurred disqualification under section 8A of the Act, as it stood immediately before the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of a State Legislature for a period of six years and his disqualification subsists upto 19-12-1980. The opinion of the Commission is now sought on a petition submitted by the returned candidate to the President for removal of the disqualification for the unexpired portion of the period of his disqualification.

2. The brief facts of the case are as follows :—

(i) The returned candidate stood as an independent candidate from the Chennur Assembly Constituency at the general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in 1972. He defeated his rival candidate Smt. N. Vimla Devi, a Congress candidate, by a margin of 1714 votes and was declared elected. His election was challenged by Smt. N. Vimla Devi before the Andhra Pradesh High Court by election petition No. 7 of 1972 in which it was alleged that the returned candidate, his agents and other persons with the consent of the returned candidate or his election agent, had committed various acts which constitute corrupt practices as defined in sections 123(1), (2), (3), (3A), (4), (5), (6) and (7) of the Act. The High Court framed 20 issues for the trial of the petition; but answered all those issues in favour of the returned candidate. Accordingly, the High Court dismissed the petition by its judgment and order dated 22-12-1972.

(ii) On appeal, the Supreme Court re-appraised the evidence afresh on one of the issues pressed before it relating to publication and distribution of a defamatory pamphlet within the meaning of section 123(4) of the Act against Smt. N. Vimla Devi by or at the instance of the returned candidate. The Supreme Court observed that the High Court had adopted an erroneous approach in the appreciation of the oral evidence and also had disbelieved the evidence led by Smt. N. Vimla Devi as being partisan but did not apply a like standard in assessing the evidence of the witnesses of the returned candidate. On re-appraisal of the evidence on the abovesaid issue, the Supreme Court came to the conclusion that the impugned defamatory pamphlet was printed and distributed at the instance of the returned candidate. Accordingly, the Supreme Court found the returned candidate guilty of the

commission of corrupt practice under section 123(4) of the Act and declared his election void on 20-12-1974. Consequently, the returned candidate also incurred disqualification under section 18A, as it then stood, for a period of 6 years, i.e., upto 19-12-1980.

3. The returned candidate has submitted the present petition on 24 October, 1977, to the President for removal of disqualification for the unexpired portion of the period of his disqualification. On 9 December, 1977, the returned candidate along with his Counsel appeared before me for a personal hearing. The Counsel urged that the disqualification of the returned candidate may be removed in the light of the following submissions :—

- (i) that the liability for publication and distribution of pamphlets has been affixed on the returned candidate vicariously;
- (ii) that the returned candidate has been an active social worker and servant of the public with spotless public career marked with faithfulness to the organisation and leadership;
- (iii) that he had been the President of the Panchayat Samithi for 10 years; but had to resign that office on his election as member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly to retain his seat in the Assembly. The result of the Supreme Court's decision has been very harsh inasmuch as he has lost his seat in the Assembly also and now he is without any public office;
- (iv) that if his disqualification is not removed now and he is not made eligible to contest the next general election to the State Assembly which is due to be held early next year, he will virtually remain disqualified for much longer period than 6 years as no election might be held thereafter for a number of years.

4. I have carefully considered the above submissions made on behalf of the returned candidate. As the Commission has already stated many times before, the Commission is bound by the findings of the Courts in such matters and cannot go into the merits of the case as made out by the parties before the Court. What the Commission has to look into in such cases is whether there are any mitigating circumstances which warrant the exercise of the discretionary power of the President to remove the disqualification before it has run its full period of 6 years. I do not find any such mitigating circumstance or special reason for exercise of the above discretionary power by the President in the present case. Nor has the returned candidate been able to

show me any such mitigating circumstance in his above submissions. The returned candidate, according to his own case, has been active in public life for a long time and he ought to know that for the maintenance of healthy political atmosphere it is absolutely necessary that no one indulges in character assassination of his opponents. And for this purpose, whether the defamatory material is published or distributed by a person himself or at his instance does not make any material difference. As regards the submission of the returned candidate about his faithfulness to the organisation and leadership, it will suffice to say that he admitted before me at the personal hearing that he was a member of the Congress party before the election but left that party to fight the election against the official candidate put up by that party. Further the plea of the returned candidate that he has been without any public office is hardly a ground for removal of the disqualification as the holding of a public office is not the prerequisite for sincere public service. Likewise, the plea that the elections might not take place for a number of years after the next general election due early in 1978 is also not a sufficient reason for removing the disqualification about 3 years in advance which will in ordinary course run upto the end of the year 1980. In view of the foregoing, I am of the opinion that the disqualification of the returned candidate should not be removed prematurely and should be allowed to subsist for the full period of 6 years. Recently, in another case (of Shri Jasdev Singh Sandhu, an ex-MLA from Punjab) which was like case of publication of pamphlet which offended the provisions of sections 123(3) and (3A) of the Act, the petition for the removal of the disqualification has been rejected by the President on the opinion tendered by the Commission.

5. In passing, I may mention that some voters of the constituency represented by one Shri Venkatanarasu, President, Farmers Service Society (Regd.), Kodakandla, Warangal District (A.P.) represented to the Commission that the present petition of the returned candidate Shri K. Madhusudan Reddy should not be accepted. I do not propose to refer to the grounds urged in their representation in view of my opinion as expressed above on the main petition of Shri Madhusudan Reddy.

6. I, accordingly, hereby tender my opinion under section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951, that the disqualification incurred by Shri K. Madhusudan Reddy should not be removed by the President under section 8A(2) of the said Act.

S. L. SHAKDHF-R, Chief Election Commissioner
of India

New Delhi :
15th December, 1977.

[No. F. 7(3)/78-Leg.II]
K. K. SUNDARAM, Secy.